

प्रेषक,

हरबंस सिंह चुध,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,  
गोपन (मंत्रिपरिषद्),  
उत्तराखण्ड शासन।

राजस्व अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 25 अप्रैल, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदान (माह 01 अप्रैल से माह 31 जुलाई, 2017 तक) के अनुदान संख्या-06 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएँ-03-कलेक्टरी स्थापना की मानक मद-23-गुप्त सेवा व्यय की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक वित्त अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक-31 मार्च, 2017 में उल्लिखित प्रदत्त निर्देशों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदान (माह 01 अप्रैल से माह 31 जुलाई, 2017 तक) के अनुदान संख्या-06 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएँ-03-कलेक्टरी स्थापना की मानक मद-23-गुप्त सेवा व्यय में प्राविधानित धनराशि ₹11,76,000=00 (रुपये ग्यारह लाख छियोत्तर हजार मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखते हुए नियमानुसार आहरण/व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28 मार्च, 2012 तथा तदकम में समय-समय पर निर्गत आदेशों के अधीन सॉफ्टवेयर से केन्द्रीय स्तर पर एक विशिष्ट नम्बर प्राप्त करने पर ही धनराशि का आहरण एवं व्यय की जाय।
2. मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। वर्ष के प्रारम्भ से ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जाय और तदनुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर, बचत सुनिश्चित की जाय।
3. धनराशि व्यय किये जाने से पूर्व जहां कोई आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फाट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न ही व्ययभार सृजित किया जायेगा।
4. भारत सरकार द्वारा आयोजनागत (Plan) तथा आयोजनेत्तर (Non-Plan) की व्यवस्था समाप्त कर राजस्व (Revenue) तथा पूंजी की व्यवस्था अपनायी गई है। राज्य सरकार द्वारा भी लेखानुदान राजस्व तथा पूंजी के अन्तर्गत ही प्रस्तुत किया गया है।
5. महालेखाकार द्वारा समय-समय पर आपत्ति के क्रम में विभिन्न विभागों के Minor Head-800 के स्थान पर नये Minor Head खोले जाने की व्यवस्था है।
6. बजट नियंत्रण अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक किश्तों में वास्तविक व्यय, आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय।
7. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम) आय-व्यय से सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

8. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में व्यय की प्रतिमाह दिनांक 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
  9. धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
  10. वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में व्यय की अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामले में सीमा से अधिक व्यय अथवा विचलन दृष्टिगोचर हो तो तत्काल संज्ञान में लाया जाय।
  11. जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाय उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख किया जाय।
  12. बजट नियंत्रण अधिकारी/विभागाध्यक्ष बी0एम0-10 प्रारूप में बजट नियंत्रण पंजी में उनके स्तर पर उपलब्ध बजट तथा उनके स्तर से अधीनस्थ अधिकारियों/आहरण वितरण अधिकारियों को आवंटित बजट का विवरण रखा जाय।
  13. इस संबंध में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/बजट नियंत्रक अधिकारी जिसके नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में प्रचलित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर पक्ष की धनराशियां जारी की जाय अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा जिसके लिए सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
02. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदान (माह 01 अप्रैल से माह 31 जुलाई, 2017 तक) के अनुदान संख्या-06 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्टरी स्थापना की मानक मद-23-गुप्त सेवा व्यय के नामे डाला जायेगा।
03. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-312/3(150)/XXVII (1)/2017, दिनांक-31 मार्च, 2017 द्वारा प्रदत्त प्राधिकार/दिशा-निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।
- संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,  
(हरबंस सिंह चुघ)  
सचिव

संख्या-398<sup>U</sup>/XVIII(1)/2017-01(30)/2016 TC एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), वैभव पैलेस, इन्द्रा नगर, देहरादून।
3. आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल पौड़ी/नैनीताल।
4. निदेशक, कोषागार, पेन्शन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
5. वित्त अधिकारी/साईबर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अधिकारी, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
9. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
(चन्दन सिंह रावत)  
उप सचिव